equity participation by other industrial undertakings in small scale units upto 24 per cent.

(c) Under the new Industrial Po licy, Government has ensured that the interest of labour would be fully protected. In order to do this, a Na tional Renewal Fund has been esta blished which will act as a social security net to protect the interest of workers against the effects of tech nology upgradation and modernisa tion.

लघु पैमाने के उद्योग

4723. **श्री वीरेन जे० शाह :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो दशकों के दौरान देश में लघु पैमाने के उद्योगों की संख्या में 250 प्रतिशत तक वृद्धि हो चुकी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में कार्यरत कुल कर्मकारों में से 38 प्रतिशत कर्मकार इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि लघु पैमाने के क्षेत्र में पूंजी निवेष बहुत कम है ;

(घ) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस क्षेत्र में उद्योगों की पूंजी निवेश सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के बारे में सरकार को अनेक सिफारिशें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) लघु औद्योगिक एककों (पंजीकृत तथा अपंजीकृत) की अनुमानित संख्या 1973–74 में 4.16 लाख थी, जो 1990–91 के अंत में बढ़कर 19.38 लाख हो गयी, जिससे इस अवधि के दौरान इनमें 365% की वृद्धि हुई है।

(ख) यद्यपि बड़े और छोटे औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार से संबंधित तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन 1990–91 के अंत में लघु क्षेत्र में 124.30 लाख रोजगार होने का अनुमान है।

(ग) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा वर्ष 1987–88 के लिए किये गए उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 1987–88 को समाप्त वर्ष में कारखाने की अचल संपत्तियों के अवमूल्यित मूल्य द्वारा यथा निरूपित प्रति श्रमिक औसत अचल पूंजी 22,125 रु० की थी, जबकि कारखाना अधिनियम में आने वाले बड़े औद्योगिक क्षेत्र में यह राशि 2,20,366 रु. थी।

(घ) और (ङ) लघु क्षेत्र में पूंजी की कमी के बारे में तथा नयी एजेंसियों की स्थापना करके और मौजूदा वित्तीय संस्थाओं के कार्य निष्पादन में सुधार करके उसकी आपूर्ति बढ़ाने के बारे में उद्योग संघों, वाणिज्य मंडलों आदि से समय-समय पर अभ्यावेदन तथा ज्ञापन प्राप्त होते हैं।

औद्योगिक रुग्णता

4724. **श्री वीरेन जे. शाह :**
डा. जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक क्षेत्र में रुग्णता की समस्या दिन प्रति दिन तेज गति से बढ़ती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो फिलहाल देश में कुल कितने रुग्ण उद्योग हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने पिछले कई वर्षों के दौरान इस रुग्णता के कारणों की पहचान करने तथा उसे ठीक करने के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करने के हेतु अनेक समितियों का गठन किया था ; और

(घ) यदि हां, तो इन समितियों का गठन कब किया गया था तथा इनकी मुख्य सिफारिशें क्या-क्या हैं और सरकार द्वारा उक्त सिफारिशों के आधार पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार, 1989 और 1990 में लघु क्षेत्र और गैर-लघु क्षेत्र में रुग्णता की स्थिति इस प्रकार थी :—

	सितंबर, 1989	सितम्बर, 1990
गैर लघु औद्योगिक रुग्ण एककों की संख्या	1,419	1,467
रुग्ण लघु औद्योगिक एककों की संख्या	1,86,441	2,25,324

(ग) औद्योगिक रुग्णता के मुद्दे का अध्ययन करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक 1981 से तीन समितियां नियुक्त कर चुका है।

(घ) भारतीय रिज़र्व बैंक ने अन्य बातों के साथ-साथ रुग्ण एककों के पुनर्वास से संबंधित मुख्य बाधाओं तथा संबंधित बैंकों व वित्तीय संस्थाओं के सामने आ रही समस्याओं का अध्ययन करने और सुधारात्मक उपायों का सुझाव देने आदि के लिए 1981 में एक समिति नियुक्त की थी। उक्त समिति ने रुग्णता की समस्याओं से निपटने के लिए एक व्यापक कानून बनाने की सिफारिश की थी । रुग्ण तथा सम्भावित रूप से रुग्ण औद्योगिक कंपनियों का समय पर पता लगाने के लिए रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 बनाया गया था तथा औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड स्थापित किया गया था ।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुग्ण लघु औद्योगिक एककों की पहचान व पुनर्वास की समस्याओं पर विचार करने के लिए फरवरी 1986 में एक और समिति नियुक्त की थी । समिति ने 31.10.1986 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । उक्त समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रारंभिक रुग्णता, रुग्ण एककों की परिभाषा, राहत तथा रियायतों के लिए मानदंडों से संबंधित थी। इन सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने फरवरी, 1987 में बैंकों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए थे । ये मार्गदर्शी सिद्धांत जून, 1989, जनवरी, 1991 और जुलाई, 1992 में पुनरीक्षित/संशोधित किए गए थे ।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अन्य बातों के साथ-साथ रुग्ण लघु औद्योगिक एककों के पुनर्वास पर विचार करने के लिए हाल में दिसंबर, 1991 में एक और समिति नियुक्त की है ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक उत्पादन की दर

4725. **श्री वीरेन जे. शाह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत निर्धारित की गई जबकि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्ष्य 8.5 प्रतिशत था ;

(ख) यदि हां, तो लक्ष्य कम निर्धारित करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास के लिए कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है और यह राशि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ निर्धारित राशि से कितनी कम अथवा अधिक है ?